

नई दिल्ली

गुरुवार

29 अक्टूबर 2026

वर्ष: 13, अंक: 55

पृष्ठ: 08, मूल्य 2 रु०

E-mail

story@sadbhawna.today

sadbhavnatoday@gmail.com

web: www.sadbhawna.today

डब्ल्यूपीएल 2027 : मिनी-ऑक्शन के बाद पांचों टीमों...पेज-06

DELHIN/2014/58158

बिहार कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी,...पेज-05



एक नगर

**पश्चिम एशिया संघर्ष में 22
भारतीयों की मौत, 14 नाविक
शामिल : विदेश मंत्रालय**

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के दौरान अब तक 22 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है, जिनमें 14 नाविक शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने बुधवार को यह भीड़िया प्रभावता में सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने इस संघर्ष पर ने संघर्ष पर गहरा चिंता जताते हुए बताया कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के दौरान अब तक 22 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है, जिनमें 14 नाविक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा और मलाई के लिए भारत उनके लगातार संपर्क में है। प्रवक्ता के अनुसार, सऊदी अरब में भी ताना भारतीयों की मौत हुई है।

भाजपा की बैठक आज, विपक्ष के खिलाफ रणनीति पर हो सकती है चर्चा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महासचिवों की एक महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार सुबह 10 बजे भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय में आयोजित की गयी है। पार्टी अध्यक्ष जितन नवीन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में देश के मौजूदा राजनीतिक हालात और मुख्य चुनाव आयुक्त एवं एसआईआर के खिलाफ विद्रोह के अभियान को लेकर आगामी राजनीति पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। पार्टी सूत्रों ने बुधवार को बताया कि बैठक में विषय की ओर से चलाए जा रहे राजनीतिक कार्यक्रमों और उनके प्रभाव को लेकर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के बीच पार्टी की राजनीति, संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी राजनीतिक रणनीतियों से निपटने की तैयारियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा पांच राज्यों में होने वाले प्रधानसभा चुनाव की तैयारियां भी बैठक का एक प्रमुख एजेंडा है। भाजपा नेतृत्व इस बैठक के जरिए आगामी चुनावों और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने पर जोर दे सकता है। बैठक में होने वाले विचार-विमर्श के आधार पर पार्टी की आगे की राजनीति और संगठनात्मक गतिविधियों की दिशा तय किए जाने की उम्मीद है।

**कोलकाता बंदरगाह पर
13.50 करोड़ रुपये से अधिक
मूल्य की ई-सिगरेट जब्त**

नई दिल्ली। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर दो अलग-अलग कार्रवाइयों में 13.50 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की ई-सिगरेट्स के बरतों को जप्त किया है। ये ई-सिगरेट नेपाल में बेचे जाने वाले दो कटेनरों में छिपाई गई थीं। अधिकारियों ने 24 अक्टूबर को खुफिया सूचना के आधार पर दोनों कटेनरों को रोका था। तब मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि एक कटेनर में सामान को 'वाटर ग्लास' और दूसरे में 'सिरेमिक माथा' के रूप में घोषित किया गया था। जांच के दौरान पहले कटेनर से आईजीईटी ब्रांड की अलग-अलग पलेवर वाली 40 हजार ई-सिगरेट बरतमंड हुईं। दूसरे कटेनर से वीटीवी, वॉको, बैंग और ईजॉय सहित विभिन्न ब्रांडों की करीब 15 हजार ई-सिगरेट मिलीं। डीआरआई ने सीमा शुल्क अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत ई-सिगरेट के साथ उन्हें छिपाने के लिए इस्तेमाल किए गए सामान को भी जब्त कर लिया।

थेनी जिला जेल से फरार 17 कैदी दोबारा गिरफ्तार: तमिलनाडु कारागार विभाग की कार्रवाई

चेन्नई, एंजेंसी। तमिलनाडु के थेनी जिला जेल से तीन ड्यूटी वार्डन पर हमला कर फरार हुए सभी 17 कैदियों को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। तमिलनाडु कारागार विभाग ने बुधवार को यह घोषणा की। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि सोमवार रात दस बजे तीसरे ब्लाक में एक कैदी को मिर्रा का दौरा पड़ने का नाटक कर कैदियों के फरार होने की घटना के तुरंत बाद 17 विशेष टीमों का गठन किया गया था।

ड्रोन सर्च ऑपरेशन सहित गहन तलाशी अभियानों के बाद, मंगलवार को इनमें से 13 कैदियों को पकड़ लिया गया था। इसके बाद बुधवार सुबह दो और कैदियों को फिर से गिरफ्तार किया गया, जबकि शाम को ड्रोन निगरानी के

जरिए ब...
भी हूँदव...
गया। इस...
17 कैदि...
जेल वाप्...
विज्ञप्...
कारागार...
महानिदेश...
आदेश प...
विशेष पु...
पुलिस (C...
जवानों में

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना टुड

दिवाली से पहले केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तोहफा, महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ा

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की



नई दिल्ली, एजेन्सी। केन्द्र के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को दिवाली को तोड़फा मिला है। सरकार ने उनके महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत का इजाफा किया है। वृद्धि इस साल की 01 जुलाई से प्रभावी मानी जाएगी। ग्राममंजरी नेरन्द मोदी को अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। केन्द्रीय मंत्री अरवुनी वैजुव ने पण्डीची मीडिया केन्द्र में पत्रकार वार्ता कर इसकी

जानकारी दी उन्होंने बताया कि इससे 48.54 लाख कर्मचारियों पर 68.71 लाख पेंशनभोगियों का लाभ मिलेगा। इससे सकारात्मक खबरों पर प्रतिक्रिया 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। वैष्णव ने कहा, 'प्रधानमंत्री की ओर से 48 लाख कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों के लिए दिवाली का उपहार है, जिसमें महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि की गई है।'

दिल्ली एसआईआर: सुप्रीम कोर्ट के निर्वाचन आयोग से कड़े सवाल

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में मतदाता सूची के 'विशेष गलत पुनरीक्षण' (एसआईआर) को कोहरे भारत निर्वाचन आयोग से कड़े सवाल पूछे। मुख्य न्यायाधीश सुर्वकत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह जानना चाहा कि जो लोग पहले से ही मतदाता के रूप में पंजीकृत थे लेकिन नई ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर छूट गए हैं, उन्हें फॉर्म 6 भरने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। यह उन्हें पहली बार के मतदाता के रूप में पेश करता है।

न्यायालय ने इस मामले पर आली सुनवाई नवंबर में करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिकृत जी. राजगोपालन ने दलील दी कि प्रशासनिक नजरिए से जो लोग नई ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें इस एसआईआर प्रक्रिया के तहत एक नई शुरुआत के रूप में देखा जाता है, इसलिए उनमें पहली बार के मतदाता की श्रेणी में रखा गया। न्यायालय ने

इस तर्क को कहा कि ये जो की मतदाता थे। याचिका वकील प्र उठेंगे। गंभीर का दिलाया। शायद लेक कि उसने में पंजीकृत पंजीकृत पर हस्ता करना आदेश घोषणा क लोक प्रतिक की धारा अपराध सजा भी न्यायालय का अधि अधिकार सावधानी

कड़ी आलोचना करते हुए
गारिक पहले से ही 2026
न्यू में सत्यापित मतदाता
नर्ताओं की ओर से वरिष्ठ
भूषण पेश हुए।

गलत के सामने एक
संकट की ओर ध्यान
में 6 मं आवेक के
यह घोषणा करनी होती है
ले कभी मतदाता के रूप
नहीं कराय। पहले से
दत्ताओं को इस दस्तावेज
के लिए मजबूर
न में उन्हें एक गलत
के लिए बाध्य करता है।
धित्व अधिनियम, 1950
के तहत ऐसा करना
जिसके लिए जेल की
सकती है। इस पर
स्पष्ट किया कि 'मतदान
एक बेहद महत्वपूर्ण
और इस मामले में पूरी
ती जानी चाहिए।

खेलों के सामान की विनिर्माण योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी, 1,856.67 करोड़ रुपये होंगे खर्च

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 2026 से 2033-34 तक के लिए 1,856.67 करोड़ रुपये की लागत से 'खेलों इंडिया खेल सामान विनिर्माण योजना' को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य देश में खेलों के सामान के निर्माण तकनीक, शोध, नवाचार और निर्यात को बढ़ा देना तथा वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति मजबूत करना है। बुधवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनि वैष्णव ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस योजना के तहत खेल सामान विनिर्माण क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जहां निर्माता, आपूर्तिकर्ता, जांच केंद्र और डिजाइन सुविधाएं एक साथ उपलब्ध होंगी। घरेलू और विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए उत्पादन बढ़ाने और निर्यात क्षमता के विस्तार से जुड़ी सहायता पर 1,130 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि योजना में छोटे और मझोले उद्योगों के मौजूदा निर्माण केंद्रों के उन्नयन, साझा सुविधाओं के विकास और अंतरराष्ट्रीय खेल महसंसों से गुणवत्ता प्रमाणन के लिए भी सहायता का प्रावधान है। प्रमाणन के लिए 105 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, खेल उपकरणों, नई सामग्रियों और आधुनिक निर्माण तकनीकों पर शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। स्टार्टअप, कौशल विकास और भारतीय खेल सामान की अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंच बढ़ाने पर भी जोर रहेगा।

**भारत-जापान ने वैश्विक
साझेदारी को और
मजबूत करने के लिए
तलाशें नए अवसर**

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजेरो कोइजुमी ने फिलीपींस के सेबू में आयोजित रक्षा मंत्रियों के बैठक एडीएमएम-प्लस से इतर द्विपक्षीय बैठक की। दोनों मंत्रियों ने अगस्त में हुई अपनी पिछली बैठक के बाद से द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों देशों की रणनीतिक और परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले इस समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चर्चा में प्रगति हुई।

बैक में समुद्री बारूदी सुरंग रोधी उपायों की क्षमता बढ़ाने, जापान की प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञता और भारत की उत्पादन क्षमताओं का लाभ उठाते हुए नौसेना पोतों के निर्माण एवं डिजाइन के क्षेत्र में संयुक्त विकास की संभावनाओं का पता लगाने पर चर्चा हुई। इस दिशा में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख की जापान यात्रा जैसे अवसरों से सहयोग को बढ़ावा मिला है।

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर इसी साल हस्ताक्षर होने की उम्मीद: सीपी राधाकृष्णन

नई दिल्ली, एंसेसी। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति सी. राधाकृष्णन ने बुधवार को उम्मीद जताया कि भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) बीच प्रस्तावित सूक्ष्म व्यापार समझौते इस साल हस्ताक्षर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 'सभी समझौतों की जगह' कारणों से हुए समझौते को अंतिम रूप देने में यूरोपीय संघ से आवश्यक सहयोग मांगा। राधाकृष्णन ने आसन्न बहव्ययी यूरोपीय संघ की विदेश मामलों की समिति (एएफसीडी) के अध्यक्ष डेविड मैकलिलिस्टर के नेतृत्व में आगामी प्रतिक्रियात्मक सं मुलाकात के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने दोनों पक्षों के नेतृत्व को इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों और खुले बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत और यूरोपीय संघ विविधतापूर्ण एवं बहुलतावादी समाज हैं। दोनों एक मजबूत और बहुधनीय वैश्व

चक्रवात अर्नब: आंध्र प्रदेश में 3 लोगों की मौत, मकान क्षतिग्रस्त

नई दिल्ली। चक्रवात 'अर्नब' पुडुचेरी के नयम के पास तट पार कर चुका है। अगले छह घंटे में इसके चक्रवाती तूफान और शाम तक गहरे दबाव के क्षेत्र में बदलने का अनुमान है। चक्रवाती तूफान का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश में हुआ है, जहाँ तीन लोगों की मौत हुई और 31 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। राज्य में हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के महानिरीक्षक नरेन्द्र सिंह बुंदेला ने बुधवार को बताया कि आंध्र प्रदेश का उत्तरी हिस्सा और ओडिशा का दक्षिणी हिस्सा चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। आंध्र प्रदेश में तीन लोगों की मौत हुई है और 31 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। राज्य में करीब 57 हजार लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है।

जुलूस ने यहाँ पत्रकारों वार्ता में कहा कि चक्रवार्ता की स्थिति को देखते हुए एक केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ और एनएसबी को मदद से मंगलवार रात आंध्र प्रदेश में चार अतिरिक्त टीमें भेजी। भारतीय वायु सेना के विमानों से इन राज्यों को पहुँचाया गया। दोनों राज्यों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने एसडीआरएफ की 80 टीमें तैनात की हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, पड़ुचेरी और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में एनडीआरएफ की कुल 39 टीमें तैनात हैं। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, ओडिशा में चक्रवार्ता का कोई गंभीर असर नहीं पड़ा है। आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। यन्म में बारिश के कारण फंसे 38 लोगों को

एनडीआरएफ की 39 टीमों तैनात



मंगलवार शाम तक सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। बुंदेला ने कहा कि चक्रवात के दौरान बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। गर्भवती महिलाओं को एहतियात के तौर पर अस्पतालों और औषधालयों में पहुँचाया जा रहा है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। मछली पकड़ने वाली नौकाओं को किनारे पर सुरक्षित रखने या अन्य सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय एजेंसियाँ लोगों को सतर्क करने और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करने में जुटी हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार सुबह चक्रवात से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने जिलाधिकारियों सहित करीब 32 हजार कर्मचारियों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस कर जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने और नुकसान कम करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात कर उन्हें राज्य में चक्रवात से हुए नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने विशाखापत्तनम, कोनासीमा, काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, एलुरु और कृष्णा जिलों की स्थिति से अवगत कराया।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन्डेर लैयेन के नेतृत्व में पूरे सरकारी तंत्र की भागीदारी के साथ हुए दौरों के बाद दोनों पक्षों के बीच संस्थागत संबंधों में मजबूत हुए हैं और इनके समन्वयक परिणाम सामने आए हैं। राधाकृष्णन ने कहा कि यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्षों ने गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया था। इसके बाद 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के लिए उनकी राजकीय यात्रा से दोनों पक्षों की साझेदारी को काफी गति मिली।

व्यापार एवं निवेश पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ का संयुक्त बाजार करीब 25,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है और इसमें लगभग दो अरब लोग शामिल हैं। उन्होंने भारत की प्रतिष्ठित 'होराइजन यूरोप' अनुसंधान एवं नवाचार योजना से जुड़े के लिए वाचिचत पूरी होने पर भी संतोष व्यक्त किया। उपराष्ट्रपति ने उच्चस्तरीय रणनीतिक समन्वय में भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग दोनों पक्षों के संबंधों को और मजबूत करेगा।

चेन्नई, एंजेंसी। तमिलनाडु के थेनी जिला जेल से तीन ड्यूटी वार्डन पर हमला कर फरार हुए सभी 17 कैदियों को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। तमिलनाडु कारागार विभाग ने बुधवार को यह घोषणा की। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि सोमवार रात दस बजे तीसरे ब्लाक में एक कैदी को मिर्रा का दौरा पड़ने का नाटक कर कैदियों के फरार होने की घटना के तुरंत बाद 17 विशेष टीमों का गठन किया गया था।

ड्रोन सर्च ऑपरेशन सहित गहन तलाशी अभियानों के बाद, मंगलवार को इनमें से 13 कैदियों को पकड़ लिया गया था। इसके बाद बुधवार सुबह दो और कैदियों को फिर से गिरफ्तार किया गया, जबकि शाम को ड्रोन निगरानी के

जरिए ब...
भी हूँदव...
गया। इस...
17 कैदि...
जेल वाप्...
विज्ञप्...
कारागार...
महानिदेश...
आदेश प...
विशेष पु...
पुलिस (C...
जवानों में

दी फरार कैदियों को रास्ता में ले लिया था ही फरार हुए सभी दोबारा गिरफ्तार कर दिया गया है। बताया गया कि वं सुधार सेवा दीप राय राठौर के थेनी सस्थान रिजर्व एवं व्यवस्था) के 7 विशेष टीमों की मदद से सभी फरार कैदियों को पकड़ा गया। इस बीच, चेन्नई के पास पुन्नल सेंट्रल जेल से 17 और थेनी जिला जेल से 17 कैदियों के भागने की दोहरी घटना बाद राज्य की सभी जेलों में कड़ी कर दी गयी है। पुलिस सशस्त्र पुलिस कमियों को किया गया है और कैदियों आवाजाही पर नजर रखने में घटनाओं की पुनरावृत्ति रोके लिए वॉच टावर बनाये गये हैं।

चाहिए और कारोबारी तथा कानूनी मामलों को लापरवाही से आसपासिक करार देना स्वीकार्य नहीं है। श्री गांधी ने इसके जवाब में सवाल करते हुए लिखा, 'प्रिय श्रीमती सीतारामण, ऐसा क्यों-सा 'कानूनी और कारोबारी मामला' था, जिसके लिए और ट्रस्ट्स और टाटा संस को अमित शाह के आवास पर बुलाना पड़ा? आपका 'नंबर एक करीबी मित्र' इस खेल में कब एंट्री लेगा और उसे टाटा का कौन-कौन सा हिस्सा मिलने वाला है? आखिर में, आपसे तीन-चार करीबी लोगों को छोड़कर, भारत के बाकी

भी कारोबारी पहले से ही आप सभी से
रत करते हैं। उन्हें किसी उकसावे की
रत नहीं है।

इससे पहले श्रीमती सीतारामण ने बुधवार
को सोशल मीडिया एक्स पर श्री गांधी को
लाह दी थी कि उन्हें हर मुद्दे का
वर्गीकरण करने से बचना चाहिए। श्रीमती
रामारामण ने यह सलाह श्री गांधी के सुबह
के बयान पर दी थी, जिसमें कांग्रेस तरीके से
लाह था, 'टाटा को आपराधिक तरीके से
बाद किया जा रहा है और कोई भी कारोबारी

पर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा।
हमारी नेताओं को कब तक चुप रहना
क्या तक, जब तक उन पर नियंत्रण
पर लिया जाये? भारतीय उद्योग
श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री
शाह की निजी संपत्ति नहीं है। हमारी
तु अपराधों के लिए न्याय सुनिश्चित
लोकसभा में विपक्ष के नेता के इस
क जवाब में श्रीमती सीतारामन ने एकस
कि श्री गांधी को हर मुद्दे का
करण करने से बचना चाहिए और

भारती तथा कानूनी मामलों को लापरवाही
 आपराधिक करार देना स्वोकार्य नहीं है।
 मैंने कहा कि श्री गांधी ने बार-बार भारतीयों
 और उद्यमियों की सफलताओं को
 तत्पर दिखाया है। उन्होंने सवाल किया कि
 श्री गांधी अब कारोबारी नेताओं को भी
 विश्वास और कुटुटा फैलाने के लिए
 वसने की कोशिश कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने
 कि कांग्रेस ने दशकों तक 'लाइसेंस-
 टा राज' के जरिये भारतीय उद्यमियों को
 बना को दबाया और करोड़ों लोगों को
 बी में रखा। इसके विपरीत, प्रधानमंत्री
 द मोदी के नेतृत्व वाली सरकार भारतीय
 उद्योग को माध्यम सृजन और आर्थिक
 विकास को माध्यम मानती है तथा उसकी
 तैयारी उद्यम, उद्योग और निवेश को बढ़ावा
 के लिए बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि
 नैतिकता दलों, नेताओं, सरकारों और
 थातों की समान जिम्मेदारी है कि वे उद्योग
 समर्थन करें, किसानों को मजबूत बनाएं
 युवाओं का भविष्य सुरक्षित करें।

भारत के संदर्भ में यूरोप की हिंसा भिन्न प्रणाली से समझनी होगी

योगेश कुमार सोनी

लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन जनता की आवाज बुलंद करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। जब सरकारें जनभावनाओं को अनसुना करती हैं, नीतियों को लेकर असंतोष बढ़ता है या लोगों को लगता है कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, तब सड़कों पर उतर कर विरोध करना स्वाभाविक है। लेकिन जब यही विरोध हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और पुलिस से टकराव का रूप ले लेता है तो सवाल केवल प्रदर्शनकारियों के उद्देश्य का नहीं रह जाता बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक स्थिरता और कानून के शासन का भी बन जाता है। यूरोप के विभिन्न देशों में समय-समय पर हुए हिंसक प्रदर्शनों से भारत को भी कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। हालांकि यूरोप एक समान राजनीतिक या सामाजिक इकाई नहीं है। फ्रांस में पेंशन सुधारों के विरोध, किसानों के आंदोलन, ब्रिटेन में दंगों और अन्य देशों में आर्थिक असंतोष से जुड़े प्रदर्शनों की परिस्थितियां अलग-अलग रही हैं। इसलिए हर घटना को एक ही नजरिये से देखने के बजाय उसके कारणों और परिणामों को समझना आवश्यक है। हिंसक प्रदर्शनों का पहला सबक यह है कि जन-असंतोष को समय रहते समझना और उसका समाधान करना किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, किसान समस्या, सामाजिक भेदभाव और भविष्य को लेकर असुरक्षा जैसे मुद्दे लोगों में नाराजगी पैदा कर सकते हैं। यदि नागरिकों को लगता है कि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है तो व्यवस्था के प्रति अविश्वास गहरा सकता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में यह चुनौती और भी महत्वपूर्ण है। यहां भाषाई, धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय और आर्थिक विविधता के कारण अलग-अलग वर्गों की अपेक्षाएं भी अलग हैं। सरकारों को चाहिए कि वे नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में जनसंवाद को प्राथमिकता दें। समय पर संवाद और शिकायतों का समाधान कई बार उस स्थिति को पैदा होने से रोक सकता है, जिसमें सामान्य विरोध उग्र हो जाता है।

हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि हर हिंसक घटना का कारण सरकारी नीतियों की विफलता नहीं होता। अफवाह, संगठित उकसावा, अपराधिक तत्व और राजनीतिक धुवीकरण भी परिस्थितियों को बिगाड़ सकते हैं। विरोध का अधिकार है, हिंसा का नहीं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि नागरिक सरकार की नीतियों से असहमति जता सकते हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, धरना, जुलूस और सार्वजनिक बहस लोकतांत्रिक व्यवस्था के आवश्यक अंग हैं लेकिन किसी नीति का विरोध करने का अधिकार सार्वजनिक संपत्ति जलाने, दुकानों को लूटने, वाहनों में आग लगाने या आम नागरिकों की सुरक्षा खतरों में डालने का अधिकार नहीं बन जाता। यूरोप की हिंसक घटनाएं यह याद दिलाती हैं कि जब विरोध की सीमा टूटती है तो सबसे अधिक नुकसान अक्सर उन्हीं आम लोगों को उठाना पड़ता है जिनके हितों की रक्षा का दावा किया जाता है। कारोबार प्रभावित होता है, सार्वजनिक परिवहन बाधित होता है, छोटे



दुकानदारों की आजीविका पर असर पड़ता है और भय का वातावरण बनता है। भारत में भी किसी आंदोलन की सफलता का मूल्यांकन केवल भीड़ के आकार या सड़कों पर पैदा हुए दबाव से नहीं बल्कि उसकी वैध मांगों, जनसमर्थन, शांतिपूर्ण आचरण और प्राप्त परिणामों से होना चाहिए।

सोशल मीडिया की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज किसी भी घटना का वीडियो कुछ ही मिनटों में हजारों-लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। सोशल मीडिया जनसमस्याओं को सामने लाने, लोगों को संगठित करने और प्रशासन तक शिकायतें पहुंचाने का प्रभावी

माध्यम है लेकिन यही माध्यम भ्रामक सूचनाओं, पुराने वीडियो को नई घटना बताकर प्रसारित करने, नफरत फैलाने और भीड़ को उकसाने का जरिया भी बन सकता है। यूरोप और भारत, दोनों के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण चुनौती है। तनावपूर्ण परिस्थितियों में बिना पुष्टि की गई खबरें आग में घी डालने का काम कर सकती हैं। इसलिए नागरिकों को किसी भी संदेश या वीडियो को साझा करने से पहले उसकी सत्यता जांचनी चाहिए। प्रशासन को भी अफवाहों का त्वरित खंडन करना चाहिए और विश्वसनीय जानकारी नियमित रूप से उपलब्ध करानी चाहिए। डिजिटल

करवा चौथ में दिनभर उपवास रखकर रात में चन्द्रमा को अर्घ्य देने के उपरान्त भोजन का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथव्रतोत्सव ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मनाती है। लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चन्द्रोदय की प्रतीक्षा करती है। सायंकाल चंद्रमा के उदित हो जाने पर चंद्रमा का पूजन कर अर्घ्य प्रदान करें। इसके पश्चात ब्राह्मण, सुहागिन स्त्रियों व पति के माता-पिता को भोजन कराएं। भोजन के पश्चात ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें। अपनी सासूजी को वस्त्र व विशेष करवा भेंट कर आशीर्वाद लें। यदि वे न हों तो उनके तुल्य किसी अन्य स्त्री को भेंट करें। इसके पश्चात स्वयं व परिवार के अन्य सदस्य भोजन करें। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी अर्थात उस चतुर्थी की रात्रि को जिसमें चंद्रमा दिखाई देने वाला है। उस दिन प्रातः स्नान करके अपने पति की आयु, आरोग्य, सौभाग्य का संकल्प लेकर दिनभर निराहार रहें। उस दिन भगवान शिव-पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रमा का पूजन करें। शुद्ध धी में आटे को सेंककर उसमें शक्कर अथवा खांड मिलाकर नैवेद्य हेतु लड्डू बनाएं। काली मिट्टी में शक्कर की चासनी मिलाकर उस मिट्टी से तैयार किए गए मिट्टी के अथवा तांबे के बने हुए अपनी सामर्थ्य अनुसार 10 अथवा 13 करवे रखें। करवा चौथ के बारे में व्रत करने वाली महिलाएं कहानी सुनती है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी।

करवा चौथ: पति-पत्नी के पवित्र रिश्तों का पर्व

रमेश सराफ़ धमोरा

भारत एक धर्म प्रधान देश है। यहां साल के सभी दिनों का महत्व है तथा साल का हर दिन पवित्र माना जाता है। करवा चौथ हिन्दुओं का प्रमुख त्योहार है। यह राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब का पर्व है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात में चन्द्रमा दर्शन के बाद सम्पूर्ण होता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलायें करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ रखती हैं। यह व्रत लगातार 12 अथवा 16 वर्ष तक हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्घापन किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहें वे जीवनभर इस व्रत को कर सकती हैं। करवा चौथ का व्रत हर साल महिलाओं द्वारा अपने पतियों के लिए किया जाता है और यह न केवल त्योंहार है बल्कि पति-पत्नी के पवित्र रिश्तों का पर्व है। कहने को तो करवा चौथ का त्योंहार एक व्रत है लेकिन यह नारी शक्ति और उसकी क्षमताओं का सवश्रेष्ठ उदहारण हैं। क्योंकि नारी अपने दृढ़ संकल्प से यमराज से भी अपने पति के प्राण ले आती हैं तो फिर वह क्या नहीं कर सकती हैं। आज के नये जमाने में भी हमारे देश में महिलायें हर वर्ष करवा चौथ का व्रत पहले की तरह पूरी निष्ठा व भावना से मनाती हैं। सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक पलियाँ अपने पति की सलामती के लिए व्रत रखती हैं। पूरे दिन बिना पानी पिएं और कुछ भी खाएं व्रत रखना आसान नहीं है लेकिन स्नेही पलियाँ अपने पति के प्रति पूरे प्रेम और सम्मान के साथ ये सभी रस्में निभाती हैं। यह त्योंहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पति की दीर्घायु एवं अखण्ड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचन्द्र गणेश जी की पूजा-अर्चना की जाती है। करवा चौथ में दिनभर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरान्त भोजन का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथव्रतोत्सव ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मनाती हैं। लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चन्द्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं। सायंकाल चंद्रमा के उदित हो जाने पर चंद्रमा का पूजन कर अर्घ्य प्रदान करें। इसके पश्चात ब्राह्मण, सुहागिन स्त्रियों व पति के माता-पिता को भोजन कराएं। भोजन के पश्चात ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें। अपनी सासूजी को वस्त्र व विशेष करवा भेंट कर आशीर्वाद लें। यदि वे न हों तो उनके तुल्य किसी अन्य स्त्री को भेंट करें। इसके पश्चात स्वयं व परिवार के अन्य सदस्य भोजन करें।

कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी अर्थात उस चतुर्थी की रात्रि को जिसमें चंद्रमा दिखाई देने वाला है। उस दिन प्रातः स्नान करके अपने पति की आयु, आरोग्य, सौभाग्य का संकल्प लेकर दिनभर निराहार रहें। उस दिन भगवान शिव-पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रमा का पूजन करें। शुद्ध धी में आटे को सेंककर उसमें शक्कर अथवा खांड मिलाकर नैवेद्य हेतु लड्डू बनाएं। काली मिट्टी में शक्कर की चासनी मिलाकर उस मिट्टी से तैयार किए गए मिट्टी के अथवा तांबे के बने हुए अपनी सामर्थ्य अनुसार 10 अथवा 13 करवे रखें। करवा चौथ के बारे में व्रत करने वाली महिलाएं कहानी सुनती है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थीं। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और



अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा बहना इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकरजी से किया था। पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण किया जाता है। सोने, चाँदी या मिट्टी के करवे का आपस में आदान-प्रदान किया जाता है। जो आपसी प्रेमभाव को बढ़ाता है। पूजन करने के बाद महिलाएं अपने सास-ससुर एवं बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेती हैं। तब शंकरजी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया।

आधुनिक होते समाज में भी महिलायें अपने पति की दीर्घायु को लेकर सचेत रहती है। इसीलिये वो पति की लम्बी उम्र की कामना के साथ करवा चौथ का व्रत रखना नहीं भूलती है। पत्नी का अपने पति से कितने भी गिले-शिकवे रहे हों मगर करवा चौथ आते-आते सब भूलकर वो एकाग्र चित्त से अपने सुहाग की लम्बी उम्र की कामना से व्रत जरूर करती है। करवा चौथ शब्द करवा अर्थात मिट्टी का बर्तन और चौथ अर्थात चतुर्थी से मिलकर बना है। इस पर्व पर मिट्टी के करवे का विशेष महत्व होता है। सभी विवाहित महिलाएं पूरे वर्ष इस त्योहार की प्रतीक्षा करती हैं और इसकी सभी रस्मों को श्रद्धा के साथ निभाती हैं। किसी भी आयु, जाति, वर्ण, संप्रदाय की सौभाग्यवती स्त्रियों को ही यह व्रत करने का अधिकार है। जो सुहागिन स्त्रियां अपने पति की आयु, स्वास्थ्य व सौभाग्य की कामना करती हैं वे व्रत रखती हैं। बालू अथवा सफेद मिट्टी की वेदी पर शिव-पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रमा की स्थापना करें। मूर्ति के अभाव में सुपारी पर नाल बांधकर ईश्वर का स्मरण कर स्थापित करें। पश्चात यथाशक्ति देवों का पूजन करें। करवों में लड्डू का नैवेद्य रखकर नैवेद्य अर्पित करें। एक लोटा, एक वस्त्र व एक विशेष करवा दक्षिणा के रूप में अर्पित कर पूजन समापन करें। दिन में करवाचौथ व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुनें। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीनकाल में एक ब्राह्मण था। उसके चार लडके एवं एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की

मंचों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के साथ-साथ हिंसा के लिए प्रत्यक्ष उकसावे और संगठित दुष्प्रचार से निपटने की जरूरत है। लेकिन इसके नाम पर वैध आलोचना को दबाना भी लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध होगा। हिंसक प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। कानून-व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना पुलिस का दायित्व है। हिंसा, आगजनी और लूटपाट करने वालों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष, अनुपातिक और जवाबदेह भी होनी चाहिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और हिंसा करने वालों के बीच स्पष्ट अंतर करना आवश्यक है। अत्यधिक बल प्रयोग, मनमानी गिरफ्तारी या किसी समुदाय के प्रति पक्षपात का आरोप व्यवस्था पर जनता के विश्वास को कमजोर कर सकता है।

भारत के लिए सबक स्पष्ट है- न तो हिंसा के सामने प्रशासन कमजोर दिखाई देना चाहिए और न ही कानून लागू करने के नाम पर नागरिक अधिकारों की अनदेखी होनी चाहिए। आधुनिक पुलिस व्यवस्था की सफलता केवल बल प्रयोग में नहीं बल्कि तनाव कम करने, संवाद स्थापित करने, खुफिया सूचनाओं के सही इस्तेमाल और समय रहते स्थिति संभालने में भी है। राजनीतिक दलों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए चूँकि लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार की नीतियों की आलोचना करना और जनता के मुद्दे उठाना है। वहीं, सत्तापक्ष का दायित्व है कि वह आलोचना को लोकतंत्र का हिस्सा माने और असहमति रखने वालों से संवाद करे। समस्या तब पैदा होती है, जब राजनीतिक लाभ के लिए किसी विवाद को भड़काया जाता है, तथ्यों के बजाय भावनाओं को उकसाया जाता है या हिंसा करने वालों के प्रति चयनात्मक रवैया अपनाया जाता है। भारत में सभी राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे विरोध प्रदर्शनों के दौरान अपने समर्थकों को शांतिपूर्ण आचरण के लिए प्रेरित करें। हिंसा किसी भी पक्ष की ओर से हो, उसकी निंदा समान रूप से होनी चाहिए। कानून का पालन राजनीतिक विचारधारा या सत्ता में मौजूद होने के आधार पर अलग-अलग नहीं हो सकता। यूरोप के हिंसक प्रदर्शनों से भारत को सबसे बड़ा सबक यह मिलता है कि लोकतंत्र केवल चुनाव कराने तक सीमित नहीं है। उसकी वास्तविक मजबूती नागरिकों के भरोसे, संस्थाओं की निष्क्षता, शांतिपूर्ण असहमति की स्वतंत्रता और कानून के समान अनुपालन में निहित है। सरकारों को जनसमस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशील होना होगा, राजनीतिक दलों को जिम्मेदार आचरण अपनाना होगा, पुलिस को निष्क्षता और संयम के साथ कार्रवाई करनी होगी तथा नागरिकों को अफवाहों और हिंसक उकसावों से बचना होगा। भारत की लोकतांत्रिक शक्ति उसकी विविधता और संवाद की परंपरा में है। असहमति को दबाने के बजाय सुनना और हिंसा को किसी भी परिस्थिति में जायज न ठहराना ही वह रास्ता है, जिससे लोकतंत्र अधिक मजबूत बन सकता है। आखिरकार, किसी भी आंदोलन का उद्देश्य व्यवस्था को बेहतर बनाना होना चाहिए, उसे हिंसा और अराजकता के हवाले करना नहीं।

विचार

कृषि मॉडल में बदलाव से ही टिकाऊ समाधान

इंदरजीत सिंह

वर्ष 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुए छह दशक से अधिक समय बीत चुका है। इसी दौर में 1966 में हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। गठन के बाद हरियाणा में बुनियादी ढांचा विकास को प्राथमिकता दी गई व हरित क्रांति को प्रोत्साहन मिला। इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन व उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। समय के साथ हरित क्रांति के विकास मॉडल की सीमाएं उजागर होने लगीं। कृषि उत्पादन में वृद्धि की संभावनाएं सिमटने लगीं तथा कई तरह के नकारात्मक परिणाम भी सामने आए। असल में तो हरित क्रांति का उद्देश्य ही पर्याप्त भूमि सुधारों के बिना कृषि क्षेत्र व फसलों का बाजारीकरण करना था। ये अलग बात है कि इससे फायदा हुआ। वर्ष 1990 के दशक में नव-उदारवादी और कॉर्पोरेट समर्थक नीतियां अपनाने के बाद कृषि संकट और गहरा गया। आज कृषि क्षेत्र को एक ऐसे वैकल्पिक विकास मॉडल की जरूरत है जो किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा भी कर सके। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता और गुणवत्ता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भारत के मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस, 2021 के मुताबिक हरियाणा की 3.64 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि क्षरण व और मरुस्थलीकरण की समस्या से प्रभावित थी। भूजल का तेजी से गिरता स्तर, सिंचाई की दोषपूर्ण पद्धतियां और गेहूं-धान का एकांगी फसल चक्र कृषि की स्थिरता के सामने गंभीर चुनौती बन गए हैं। इसके अतिरिक्त, गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण खेती का क्षेत्रफल भी घट रहा है। उपजाऊ कृषि भूमि का इस तरह लगातार कम होना खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका के लिए चिंताजनक है। जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौती कृषि संकट को और गंभीर बना रही है। बेमौसम बारिश, अत्यधिक गर्मी और अन्य चरम मौसमी घटनाओं से फसलों को बार-बार नुकसान हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की किसानों को राहत देने में प्रभावशीलता पर भी सवाल उठे हैं। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि खेती की बढ़ती लागत के अनुरूप नहीं।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अर्थशास्त्र विभाग के हालिया अध्ययनों में किसानों को होने वाले नुकसान की गंभीर तस्वीर सामने आई है। खरीफ फसलों की वर्कशाप में जानकारी दी गई कि धान की पीआर किस्म की खेती में किसान का प्रति एकड़ घाटा करनारल में 4285 रुपये आंका गया। बीटी कपास में किसान को प्रति एकड़ औसत घाटा 15,143 रुपये था, जबकि मक्का की खेती में 1229 रुपये प्रति एकड़ रहा। कपास जैसी महत्वपूर्ण फसल की काशत की स्थिति तो और भी तेजी से गिरावट पर है। वर्ष 2025-26 में ही कपास के रकबे में 2.82 लाख हेक्टेयर की गिरावट दर्ज की गई। पिछले सात वर्षों में कपास की खेती के क्षेत्रफल में 65 प्रतिशत की कमी आई है। इसका एक प्रमुख कारण बी टी कपास पर गुलामी सूंडी के प्रकोप से फसल बर्बादी है। बहरहाल, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, कुपोषण, भूमिहीनता, कर्ज और बेरोजगारी की समस्याएं बढ़ी हैं। खाद की कमी, मंडी में फसल बेचने की दिक्कतें और खरीद संबंधी बाधाएं अब किसानों के विरोध-प्रदर्शनों के प्रमुख मुद्दे हैं। हरियाणा और पंजाब में कृषि का मौजूदा मॉडल अब टिकाऊ नहीं रहा। यह स्थिति छोटे और सीमांत किसानों के लिए अधिक संकटपूर्ण है। हरियाणा में छोटे और सीमांत किसान कुल कृषि परिवारों का लगभग 70 प्रतिशत हैं। इनकी समस्याओं की अनदेखी तो साधान उत्पन्न में आत्मनिर्भरता बनाए रखना कठिन हो सकता है। इसके साथ ही कुछ जानकारों की चर्चाओं में सामने आया कि सरकारी खरीद व्यवस्था लगातार कमजोर हुई है। यह भी कि भंडारण क्षमता के निवेश में लगातार कमी की गयी। निजी क्षेत्र को भंडारण क्षेत्र में अनुमति देने का खमियाजा किसानों और कृषि मजदूरों को भुगतान पड़ रहा है। वे मनमर्जी से बाजार को संचालित करेए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली कमजोर हो जाएगी। इस संकट से उबरने के लिए एक व्यापक, किसान-हितैषी और टिकाऊ वैकल्पिक कृषि नीति अपनाना समय की मांग है। तत्काल राहत के लिए उन किसानों के कर्ज माफ किए जाने चाहिए जो उन्हें चुकाने में असमर्थ हैं, खेती की लागत कम करने के लिए, प्रभावी कदम उठाएं जाने चाहिए, स्वामीमता आयोग की सिफारिश के अनुरूप सी 2+50 प्रतिशत के फार्मुले पर न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण पर प्रभावी रोक लगे। कृषि संकट के स्थायी समाधान के लिए ऐसी वैकल्पिक कृषि नीति की आवश्यकता है जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करे, फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे, लागत खर्च घटाए, कीट रोधक व चरम मौसम को झेलने वाले नए बीजों और अन्य अनुसंधानों को प्राथमिकता दें।

एक नजर

सुरक्षित बचपन अभियान के तीसरे दिन भी विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित



सुपौल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से परिकल्पित सुरक्षित बचपन अभियान के तहत बुधवार को जिले के विभिन्न विद्यालयों में तीसरे दिन भी विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आयोजित इन कार्यक्रमों में सुपौल के साथ-साथ वीरपुर एवं निर्मली अनुमंडल के विद्यालयों में बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राजेश कुमार बच्चन के मार्गदर्शन में संचालित इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी देने के साथ उनमें आत्मविश्वास विकसित करना है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को अपनी बात खुलकर रखने, सवाल पूछने तथा बाल सुरक्षा से जुड़े विषयों पर अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से बच्चों को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें वे अपनी समस्याओं को बिना किसी डर या संकोच के सामने रख सकें। साथ ही, उन्हें बाल अधिकारों के प्रति जागरूक बनाकर किसी भी असुरक्षित स्थिति में आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल के सचिव अमित गौरव ने कहा कि बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ अपनी समस्याएं साझा करने और निर्भीक होकर बोलने के लिए प्रोत्साहित करना इस अभियान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि बच्चों में जागरूकता और आत्मविश्वास विकसित होने से उनके संरक्षण की दिशा में सार्थक पहल की जा सकती है। अभियान के तहत जिले के विभिन्न विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित बचपन, अधिकारों और संरक्षण के प्रति जागरूक करने का प्रयास जारी है।

एसएसबी में फिट इंडिया फ्रीडम रन 7.0 के तहत जॉगिंग कार्यक्रम आयोजित



सुपौल। रिक्रट प्रशिक्षण केंद्र, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), सुपौल में बुधवार को फिट इंडिया फ्रीडम रन 7.0-2026 के तहत ‘फिटनेस की डोज, आशा रोज’ अभियान के अंतर्गत जॉगिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसएसबी के अधिकारियों एवं कर्मिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और निर्धारित मार्ग पर जॉगिंग कर नियमित व्यायाम का संदेश दिया। इस दौरान अधिकारियों एवं जवानों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम, जॉगिंग और विभिन्न खेल गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और शारीरिक सक्रियता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कर्मिकों में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा उन्हें फिट और सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस पहल के जरिए नियमित शारीरिक गतिविधियों को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया गया।

डॉ. एन.के. यादव की हैट्रिक जीत पर वाईएनपी डिग्री कॉलेज में हर्ष, भाजपाईयों ने मनाया जश्न

अररिया। कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी डॉ. एन.के. यादव की लगातार तीसरी बार जीत पर भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित हैं।जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया ढोल बाजे के साथ समर्थकों का मुँह मीठा कराया गया।डॉ एन.के.यादव के जीत पर रानीगंज वाईएनपी डिग्री कॉलेज में हर्ष और उत्साह का माहौल रहा। महाविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मियों ने उनकी जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. नूतन आलोक ने डॉ. यादव की जीत पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि डॉ. साहब ने जीत की हैट्रिक लगाई है। उनकी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पित भाव से की गई सेवा का ही प्रतिफल है कि उन्हें बड़े अंतर से जीत हासिल हुई है। महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य डॉ. अशोक कुमार आलोक ने कहा कि इस चुनाव में सभी जातियों के लोगों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर डॉ एन.के. यादव के पक्ष में मतदान किया। उनकी जीत जन विश्वास और व्यापक जनसमर्थन का प्रतीक है। इस अवसर पर हर्ष व्यक्त करने वालों में प्रो. नवल किशोर सहाय, प्रो. इंदु कुमारी, प्रो. सुभाष चंद्र सिंह, प्रो. भूषण कुमार यादव, प्रो. योगेंद्र प्रसाद यादव, प्रो. प्रमोद कुमार यादव, प्रो. पिंकी प्रेमा, रितेश राज, दीपेश राज एवं आदित्य कुमार सहित अन्य लोग प्रमुख रूप से शामिल हैं।

डीएम ने जोकीहाट में विभिन्न कार्यालयों का किया निरीक्षण

अररिया। डीएम विनोद दूहन ने बुधवार को जोकीहाट प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, मनरेगा कार्यालय तथा बाल विकास परियोजना कार्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने विभिन्न कार्यालयों में संधारित पंजियों एवं अभिलेखों का अवलोकन किया तथा कार्यालयों में संचालित कार्यों के निष्पादन की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अभिलेखों का सुव्यवस्थित एवं अद्यतन संधारण सुनिश्चित करने, कार्यालयी प्रक्रियाओं का नियमानुसार अनुपालन करने तथा सरकारी कार्यों का समयबद्ध निष्पादन करने के निर्देश दिए। इस क्रम में जिला पदाधिकारी ने आरटीपीएस काउंटर का भी निरीक्षण किया तथा वहां उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कार्यालय में उपस्थित आम नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं कार्यों के निष्पादन से संबंधित जानकारी प्राप्त की। जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देशित किया कि आम नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखने तथा आम लोगों को सुलभ, सुगम एवं बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया।

बिहार कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी, पटना में भूमिगत सड़क कॉरिडोर की संभावनाओं का होगा अध्ययन

- ☐ बिहार एमएसएमई नीति 2026 को मंजूरी, पांच वर्षों में एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य
- ☐ सोनपुर आयोजना क्षेत्र का होगा विस्तार, ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटेगी

पटना, एंजेसी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार शाम हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें पटना में भूमिगत सड़क कॉरिडोर की संभावनाओं का अध्ययन, सोनपुर आयोजना क्षेत्र का विस्तार, बिहार एमएसएमई नीति 2026, औद्योगिक निवेश और बिजली विभाग की योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि पटना में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से भूमिगत सड़क कॉरिडोर विकसित करने की संभावनाओं का अध्ययन कराया जाएगा। इसके तहत आर ब्लॉक चौराहे से कंकड़बाग और डाकबंगला चौराहे से पटना वीमेस कॉलेज सहित शहर के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को भूमिगत मार्गों से जोड़ने की व्यावहारिकता का आकलन किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल केवल संभाव्यता अध्ययन को मंजूरी दी गई है। भूमिगत सड़क कॉरिडोर के निर्माण की स्वीकृति अभी नहीं दी गई है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सोनपुर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप, अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, फिल्म सिटी, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य विकास परियोजनाओं का ध्यान में रखते हुए सोनपुर आयोजना क्षेत्र के विस्तार को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही

चुनाव जीतने के बाद नीरज कुमार ने लिया नीतीश कुमार का आशीर्वाद

पटना। बिहार विधान परिषद के पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार चौथी बार जीत दर्ज करने के बाद जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने बुधवार को 7, सर्कुलर मार्ग स्थित आवास पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया।

इस अवसर पर नीतीश कुमार ने उन्हें जीत के बधाई एवं शुभकामनाएं दीं तथा ‘न्याय के साथ विकास’ के मूलमंत्र के अनुरूप जनसेवा के कांछों को निरंतर आगे बढ़ाने और जनता के विश्वास पर हमेशा खरा उतरने का कहा। पार्टी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल-मालाओं से लाद दिया। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार, निशांत एवं नीरज कुमार के समर्थन में जोरदार नारे लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर नीरज कुमार ने अपनी जीत का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री निशांत की विकासपरक जोड़ी को देते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन, नीतियों और सिद्धांतों ने इस जीत को संभव



बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा, नेतृत्व के प्रति जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं के समर्पण का ही परिणाम है कि उन्हें लगातार चौथी बार जीत हासिल हुई है। नीरज कुमार ने इस शानदार जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी अथक मेहनत, निष्ठा और समर्पण के बिना यह सफलता संभव नहीं थी। चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं ने दिन-रात एक कर जनसंपर्क अभियान चलाया और पूरी प्रतिबद्धता के साथ उनकी जीत सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई। इस अवसर पर विधान परिषद् में सत्तारूढ़ दल के उप-नेता ललन कुमार सराफ, मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी, प्रदेश महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी अरुण वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता चंदन कुमार सिंह, छात्र जदयू के पूर्व अध्यक्ष राधे श्याम व अन्य नेतागण उपस्थित थे।

मुर्गी और मछली फार्म संचालक की संदिग्ध हालत में मिला शव,गांजा तस्करी में हत्या की आशंका,पुलिस जांच में जुटी

अररिया। जिले के घूरना थाना क्षेत्र के पथराहा पंचायत के वार्ड-14 में बुधवार को मुर्गी और मछली फार्म चलाने वाले 45 वर्षीय इजरायल उर्फ धरमा का शव भारत-नेपाल सीमा के पास संदिग्ध हालत में मिला। शव सीमा सड़क से नहर चौक जाने वाले रास्ते पर मतेबुल रहमान के घर के पास मिला। यपरिजनों ने गांजा तस्करी से जुड़े विवाद में हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने शरीर पर चोट के निशान होने की बात भी कही है। सूचना के बाद मौके पर घूरना थानाध्यक्ष सुमन कुमारी पुलिस अधिकारी और बलों के साथ मौके पर पहुंची और मामले की तपतीश शुरू कर दी।एफएसएल की टीम को बुलाया गया,जिन्होंने मौके से कई सैंपल कलेक्ट किए। परिजनों के अनुसार, मंगलवार शाम से ही धरमा गायब था। पंचायत सरकार भवन के पास उनका मुर्गी और मछली फार्म था। इसी से वह परिवार का खर्च चलाते थे। काफी खोजने के बाद भी उनका पता नहीं चला तो परिजनों ने घूरना थानाध्यक्ष सुमन कुमारी को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की।

परिजनों ने बताया कि बुधवार को कुछ लोग धरमा को सीमा सड़क के पास लेकर आए। उन्होंने परिवार वालों से कहा कि धरमा निम्ता है, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। इसके लिए चारपहिया गाड़ी भी मंगाई गई। इसी दौरान परिजनों ने उनका नब्ब जांची तो पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है।



ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में भूमि की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया गया है। अरविंद चौधरी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 'एक करोड़ उद्यमी परिवार, सशक्त बिहार का आधार' के उद्देश्य से बिहार एमएसएमई नीति 2026 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत अगले पांच

वर्षों में एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से एक करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके अलावा राज्य के साख-जमा अनुपात को 75 प्रतिशत तक पहुंचाने, प्रत्येक जिले में कम से कम एक औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने और सभी 38

सोन बेसिन में जल उपलब्धता के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू, राज्यों से मांगे गए आंकड़े

डेहरी आन सोन। सोन नदी बेसिन में अतिरिक्त जल की उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने बेसिन से जुड़े राज्यों से प्रमुख जल परियोजनाओं के दीर्घकालिक आंकड़े मांगे हैं।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा के पत्र के जवाब में यह जानकारी दी है। वहीं, आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने के कारण जमानिया पंप नहर योजना के प्रस्ताव को राज्य सरकार को वापस माना गया है। सांसद उपेंद्र कुशवाहा के अनुसार गत 26 अगस्त को केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर वर्ष 1973 के बाणसागर एकरारनामा के तहत सोन बेसिन में उपलब्ध अतिरिक्त जल का आकलन करने और राज्यों के बीच जल का पुनर्निर्धारण कराने का अनुरोध किया था। उन्होंने जमानिया पंप नहर योजना को केंद्रीय जल आयोग से अंतिम स्वीकृति दिलाने का मुद्दा भी उठाया था। केंद्रीय मंत्री के पत्र के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी चोपन स्थल पर पूर्व में किए गए जल विज्ञान संबंधी प्रैक्शों के आधार पर सोन बेसिन में अतिरिक्त जल उपलब्ध होने की संभावना जताई थी। राज्य सरकार ने इसके पुनर्मूल्यांकन की मांग की थी।

इस मामले में आठ मई 2026 को केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। बैठक में सोन नदी बेसिन से जुड़े सभी राज्यों ने जल उपलब्धता के पुनर्मूल्यांकन के लिए सैद्धांतिक सहमति दी थी। इसके बाद



प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए गत 12 अगस्त को मुख्य अभियंता (हाइड्रोलॉजी) की अध्यक्षता में एक और बैठक आयोजित की गई।

पुनर्मूल्यांकन के लिए राज्यों से इंद्रपुरी बराज , रिहंद बांध, बाणसागर बांध और ओबरा बांध जैसी प्रमुख परियोजनाओं के संचालन शुरू होने की तिथि से अब तक के अंतर्वाह (इनफ्लो), अतिरिक्त जल के बहाव (स्पिल) और जल उपयोग से संबंधित दीर्घकालिक आंकड़े मांगे गए हैं। इन आंकड़ों को 10-दिवसीय श्रृंखला प्रारूप में उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके अलावा भविष्य में प्रस्तावित जल परियोजनाओं का विवरण भी मांगा गया है। सांसद कुशवाहा ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्यों से आवश्यक आंकड़े

जिलों में एमएसएमई केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कैबिनेट ने गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर में ग्रीन बेस्ट एथेनॉल उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 97 करोड़ 80 लाख 18 हजार रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस इकाई की स्थापना से 210 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। वहीं, किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में इमेज स्टार्च उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 88 करोड़ 62 लाख रुपये के पूंजी निवेश को स्वीकृति दी गई है। इससे 217 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर स्थित बंद चीनी मिल की जमीन के औद्योगिक उपयोग को भी मंजूरी दी है। बिहार राज्य चीनी निगम की इस इकाई की जमीन में से 115.08 एकड़ पर चीनी मिल की स्थापना की जाएगी, जबकि शेष 151.58 एकड़ जमीन उद्योग विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। इस भूमि का उपयोग सात निश्चय-3 के अंतर्गत 'समुद्ध उद्योग-सशक्त बिहार' कार्यक्रम के तहत नए उद्योगों की स्थापना और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बिजली विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 11 हजार 96 करोड़ 55 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा आर्थिक अपराध इकाई के बढ़ते कार्यभार को देखते हुए 143 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। राज्य के नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं से संबंधित जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इसके क्रियान्वयन के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का चयन किया गया है। इस योजना पर दो करोड़ 34 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

सोन बेसिन में जल उपलब्धता के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू, राज्यों से मांगे गए आंकड़े



प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए गत 12 अगस्त को मुख्य अभियंता (हाइड्रोलॉजी) की अध्यक्षता में एक और बैठक आयोजित की गई।

पुनर्मूल्यांकन के लिए राज्यों से इंद्रपुरी बराज , रिहंद बांध, बाणसागर बांध और ओबरा बांध जैसी प्रमुख परियोजनाओं के संचालन शुरू होने की तिथि से अब तक के अंतर्वाह (इनफ्लो), अतिरिक्त जल के बहाव (स्पिल) और जल उपयोग से संबंधित दीर्घकालिक आंकड़े मांगे गए हैं। इन आंकड़ों को 10-दिवसीय श्रृंखला प्रारूप में उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके अलावा भविष्य में प्रस्तावित जल परियोजनाओं का विवरण भी मांगा गया है। सांसद कुशवाहा ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्यों से आवश्यक आंकड़े

प्राप्त होने के बाद ही सोन बेसिन में जल उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन पूरा हो सकेगा। इसके बाद संबंधित राज्यों की सहमति से अतिरिक्त जल के पुनर्निर्धारण की दिशा में आगे की कार्रवाई की जा सकती है। जमानिया से ककरीत गंगाजल लिफ्ट सिंचाई योजना से संबंधित जमानिया पंप नहर परियोजना के मामले में केंद्रीय जल आयोग को अपेक्षित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। मंत्री के अनुसार, आयोग की ओर से कई बार अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद आवश्यक जानकारी नहीं मिली। इस कारण प्रस्ताव को राज्य सरकार को वापस किया हुआ मान लिया गया है। साथ ही, इसे केंद्रीय जल आयोग के परीक्षणधीन प्रस्तावों की सूची से भी हटा दिया गया है।

भारतीय नवम्बर के वाहनों को नेपाल में रखकर सीमा पर तस्करी का खेल

अररिया। जोगबनी के भारत नेपाल सीमा पर सक्रिय तस्कर नेपाली नंबर के वाहन के जगह अब तस्करी के लिए भारतीय नंबर के वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं।इसका खुलासा नेपाल सशस्त्र पुलिस बल के द्वारा

17अक्टूबर 2026 को मुख्य सीमा पर जब्त की गई भारतीय नम्बर की वाहन के बाद हुआ है। मोरंग शस्त्र पुलिस बल के एसपी गहेन्द्र भंडारी के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 की दोपहर नेपाल भारत सीमा के मटेरुवा सीमा पर नियमित गश्ति के दौरान सशस्त्र पुलिस के एक दल ने भारतीय नंबर प्लेट की एक हुंडई वेन्यू कार को संदिग्ध अवस्था में पाया।सुरक्षाकर्मियों ने जब रोकने का प्रयास किया तो चालक गाड़ी रोकने के बजाय भगा ले गया। चक्रमा देकर भागी बीआर 38 एपी 8286 नंबर की वह कार उसी दिन जोगबनी रानी विराटनगर सीमा के एक नंबर गेट के पास मिली। गाड़ी नेपाल की तरफ से ही सीमा शुल्क गेट की तरफ जा रही थी और चालक ऐसा नाटक कर रहा था मानो वह अभी भारत से नेपाल प्रवेश किया है।चालक सीमा शुल्क छूट पच्ची बनवाने के फिराक में था। सशस्त्र पुलिस ने तुरंत घेरेकर गाड़ी को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, लेकिन चालक गाड़ी की चाबी लेकर फरार हो गया। परिजनों के अनुसार, धरमा ही परिवार में कमाने वाले था। मामले पर घूरना थानाध्यक्ष सुमन कुमारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम कराया गया है।पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगा।कई बिंदुओं पर पुलिस की जांच की जा रही है।

सशस्त्र पुलिस, मोरंग के एसपी गेहेन्द्र बहादुर भंडारी पर वैध रूप से सीमा शुल्क सुविधा लेकर चलाई जा रही गाड़ी को कब्जे में लेकर नौ दिनों तक परेशान करने का आरोप लगाया।

लेकिन,आरोप निराधार निकला। भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 56वीं बटालियन की ओर से नेपाल पुलिस द्वारा मांगी गई सूचना उपरांत भेजे गए पत्र में जोगबनी स्थित बॉर्डर चेक पोस्ट से उक्त नंबर की गाड़ी के नेपाल प्रवेश नहीं होने की जानकारी दी गई। एसएसबी का पत्र आने के बाद,मामले में अनुसंधान से जुड़े उच्च अधिकारियों का कहना है कि तस्करों की सीमा शुल्क विभाग के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलीभगत है। अधिकारियों के अनुसार, गाड़ी को नेपाल में ही छिपाकर रखने और सीमा शुल्क से केवल कागजी एंट्री कराने का पुराना तरीका ही इस्तेमाल किया जा रहा है। उस अधिकारी ने कहा,फिर नेपाल प्रवेश की छूट पच्ची मिलने के बाद वे भारत में एंग्रिज किए बिना हर दिन छूट पच्ची कटाते हैं। गाड़ी कभी भारत नहीं जाती, गाड़ी नेपाल में ही रहती है। मोरंग के सशस्त्र पुलिस प्रमुख गहेन्द्र बहादुर भंडारी ने बताया कि उस गाड़ी के भारत से नेपाल प्रवेश करने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। उन्होंने कहा कि एसएसबी की एंट्री बुक में भी वह गाड़ी नहीं है। उसने हमें पुष्टि पत्र भी दिया है कि यह गाड़ी एंट्री नहीं हुई है। पुराने रिकॉर्ड में भी नहीं है। लेकिन उस दिन का हम कन्फर्मेशन लेटर ही लेकर आए हैं।

एक नजर

इजराइल में चुनावी धांधली के आरोप, नेतन्याहू की लिकुड ने जांच की मांग की

यरुशलम,एजेंसी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी लिकुड ने चुनाव में व्यापक धांधली और मतदाताओं को डराने–धमकाने के आरोप लगाते हुए पुलिस और आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट से जांच की मांग की है। पार्टी ने दावा किया कि चुनाव में अरब दलों ने कथित आपराधिक गतिविधियों के जरिए नतीजों को प्रभावित किया। लिकुड ने अपने बयान में रिश्तत, धमकी, हिंसा, जालसाजी और मतदाताओं को जुटाने के लिए अवैध सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल जैसे आरोप लगाए। पार्टी का कहना है कि उसने पुलिस, शिन बेट और केंद्रीय चुनाव समिति को सैकड़ों गवाहियां तथा अन्य साक्ष्य सौंपने की बात कही है। इनमें नकदी और राआम पार्टी की पर्चियों वाले लिफाफे, मतदान केंद्रों पर कथित हिंसा, एक से अधिक बार मतदान और मतदाता संख्या तथा मतपत्रों के आंकड़ों में विसंगतियों के आरोप शामिल हैं। अरब नेतुत्व वाले राआम और ज्वाइंट लिस्ट दलों को चुनाव में रिकॉर्ड मत मिलने और 19 सीटें हासिल करने का अनुमान बताया गया है। इससे नेतन्याहू के गठबंधन और उनके विरोधी यहूदी–नेतुत्व वाले दलों, दोनों के लिए संसद में बहुमत जुटाना मुश्किल होने की बात कही गई है। चुनाव प्रचार के दौरान लिकुड ने अरब दलों के साथ राजनीतिक सहयोग का विरोध किया था। पार्टी ने अब पूरे मामले की गहन जांच और केंद्रीय चुनाव समिति से तत्काल जवाब मांगा है। हालांकि, चैनल 12 को दिए एक साक्षात्कार में केंद्रीय चुनाव समिति के एक अधिकारी ने चुनावी धांधली के दावों को खारिज किया। ऐसे में आरोपों की जांच और आधिकारिक निष्कर्षों पर आगे की स्थिति निर्भर करेगी।

इटली में प्रदर्शन में हिंसा भड़काने का आरोपित रिहा, मेलोनी ने फैसले को बताया शर्मनाक



मिलान। इटली में हिंसक प्रदर्शनों को कथित तौर पर भड़काने के आरोप में गिरफ्तार 30 वर्षीय स्वतंत्र पत्रकार और शोधकर्ता यूसुफ सिहर को अदालत ने रिहा करने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए इसे 'शर्मनाक' करार दिया और कहा कि इससे पुलिस तथा जांचकर्ताओं के काम का अपमान हुआ है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जारी वीडियो संदेश में कहा, 'यह एक शर्मनाक फैसला है। मेरे विचार से यह पुलिस बल, जांच अधिकारियों और गृह मंत्रालय के काम का असहनीय अपमान है। ये सभी लोग आम नागरिकों को इस खतरे से बचाने के लिए प्रयासरत हैं कि उनके शहरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठाओं में तोड़फोड़ की जाए। मोरक्को मूल के इतालवी नागरिक सिहर को 24 अक्टूबर को मिलान के अभियोजकों ने अपराध के लिए उसकासे और कथित आतंकवादी उद्देश्यों से जुड़े आरोपों में हिरासत में लिया था। पुलिस के मुताबिक, वह 'अक्टूबर 17 मूवमेंट' नामक टेलोग्राम समूह का प्रशासक था। यह समूह मिलान में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद बनाया गया था। हालांकि, मामले की सुनवाई कर रहें न्यायाधीश तिजियाना लांडोनी ने जांच में गंभीर खामियों की ओर इशारा किया। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि सिहर के खिलाफ लगाए गए अपराधों में उसकी सलिसता मानने के लिए पर्याप्त गंभीर आधार नहीं हैं और उसके फरार होने का जोखिम भी नहीं है। अदालत के अनुसार, विवादित संदेश समूह के अन्य सदस्यों ने पोस्ट किए थे। सिहर के हिंसक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने या उनका समर्थन करने के प्रमाण नहीं मिले। सिहर ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है।

नेपाल में पर्यटक वीजा का दुरुपयोग करके धर्मांतरण कराने के आरोप में 10 विदेशी गिरफ्तार

काठमांडू। नेपाल में पर्यटक वीजा का दुरुपयोग कर धर्मांतरण के लिए शिविर संचालित करने के आरोप में 10 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें मोरंग जिले के कानेपोखरी स्थित बरागाछी में ईसाई धार्मिक गतिविधियों के प्रचार में सलिसत होने के आरोप में पकड़ा गया है। गिरफ्तार लोगों में ब्राजील, कनाडा और अमेरिका के नागरिक शामिल हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार 'मर्सी डेवलपमेंट' नामक संस्था की ओर से पर्यटक वीजा पर नेपाल आए विदेशी चिकित्सकों



सहित 10 विदेशी नागरिक स्वास्थ्य शिविर संचालित कर रहे थे। उनके दस्तावेज जब्त कर आवश्यक कार्रवाई के लिए आब्रजन विभाग भेज दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि आवश्यक अनुमति लिए बिना पर्यटक वीजा पर आए विदेशी नागरिक शिविर में शामिल थे। इस कारण विदेशी नागरिक निगरानी जिला समिति के निर्णय के अनुसार उनके पासपोर्ट आवश्यक कार्रवाई के लिए विभाग भेजे गए हैं। यह शिविर 25 अक्टूबर से चार दिनों तक संचालित करने की योजना के साथ शुरू किया गया था। इसमें 10 विदेशी नागरिकों सहित अन्य लोग सेवाएं दे रहे थे। शिविर की तैयारी पास्टर पावेल दंगाल ने की थी। स्थानीय स्तर पर अस्पताल बनाने के उद्देश्य से इस्तेमाल की जाने वाली बताई गई जमीन पर इससे पहले पास्टर बादिल ईसाई धार्मिक कक्षाएं संचालित करते थे। मोरंग जिले के कानेपोखरी, बरागाछी के किराना व्यवसायी नवराज श्रेष्ठ ने अस्पताल निर्माण के उद्देश्य से तीन कट्ठा जमीन पर छह छोटे–बड़े भवन बनवाए थे। फिलहाल उन्हीं भवनों का इस्तेमाल धार्मिक गतिविधियों और अन्य कार्यक्रमों के लिए किया जा रहा था। इसी मुद्दे को लेकर उत्पन्न विवाद को शांत करने के लिए व्यवसायी श्रेष्ठ ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया था। आब्रजन विभाग के अनुसार संबंधित विदेशी नागरिक 22 और 23 अक्टूबर को नेपाल आए थे। उनके वीजा की वैधता अवधि 6 से 21 नवंबर तक थी। वीजा का दुरुपयोग कर धर्म प्रचार करने के आरोपों के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

बेंजामिन नेतन्याहू ने किया मजबूत दक्षिणपंथी सरकार बनाने का आह्वान

यरुशलम,एजेंसी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार तड़के एक मजबूत दक्षिणपंथी सरकार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने अरब पार्टियों पर निर्भर सरकार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। यहां लिकुड पार्टी के चुनाव मुख्यालय में कार्यकर्ताओं और पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एफिजट पोल से नतीजे स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। इसलिए अंतिम गिनती का इंतजार करना चाहिए।

द यरुशलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, नेतन्याहू ने कहा, ‘लिकुड इजराइल की सबसे बड़ी पार्टी है।’ उन्होंने यह भी दावा किया कि यहूदी और जायोनी जनता के बीच और जो लोग यहूदी राज्य का समर्थन करते हैं, उनके बीच दक्षिणपंथी गुट को निर्णायक बहुमत हासिल है। नेतन्याहू ने कहा, ‘हमें एक मजबूत, दक्षिणपंथी, राष्ट्रीय सरकार बनानी चाहिए। उन्होंने ऐसी सरकार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी जो उनके शब्दों में ‘जायोनी–विरोधी’ अरब पार्टियों पर निर्भर हो। उन्होंने इन पार्टियों पर इजराइल के अस्तित्व का विरोध करने और उसके सैनिकों पर हमले करने का आरोप लगाया। उन्होंने उन राजनेताओं को चुनौती दी जो सेना में सेवा देने वालों के गठबंधन की वकालत करते हैं और उनसे पूछा कि वे इन अरब पार्टियों के साथ सहयोग करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। नेतन्याहू ने अपनी सरकार की सैन्य उपलब्धियों और अथुरे कामों का जिक्र किया। उन्होंने ईरानी खतरे को दूर करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करने के एक मौके



का जिक्र किया। इस बीच लिकुड पार्टी के निवर्तमान सांसद अमित हलेवी ने नेतन्याहू के गुट के लिए शुरुआती अनुमान में बताई गई 50 सीटों पर सवाल उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि यह उनके समर्थन को कम करके दिखाता है और यह अंतिम परिणाम नहीं होगा। उन्होंने इस चुनाव को 7 अक्टूबर के हमलों और तीन साल के युद्ध के प्रति इजराइली समाज की प्रतिक्रिया बताया। हलेवी ने अरब पार्टियों की संभावित

ताकत की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक प्रभाव पर उनकी आपत्ति उनकी जातीयता को लेकर नहीं, बल्कि उनकी ‘कट्टरपंथी विचारधारा’ को लेकर है। इस दौरान लिकुड के पुराने सदस्य मीर कोहेन से पूछा गया कि नेतन्याहू इस अनिश्चितता से कैसे निपटेंगे और सरकार कैसे बनाएंगे तो उनका जवाब बहुत सीधा था। उन्होंने कहा, ‘मुझे नेतन्याहू पर भरोसा है।

स्पेन में रेल हादसे में 64 लोगों की मौत, कई देशों ने जताई संवेदना



मैड्रिड। स्पेन के टोलेडो प्रांत में दो ट्रेनों की टक्कर में कम से कम 64 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सरकार के कास्तिया–ला मांचा प्रशासन के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने आशंका जताई कि घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी रहने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हादसे के बाद यूरोप के कई देशों के नेताओं ने शोक व्यक्त करते हुए पीड़ितों और उनके परिजनों के प्रति संवेदना जताई।

पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुईस मोंटेग्रेयो ने प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और जरूरत पड़ने पर हरसंभव सहायता देने की पेशकश की। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने पीड़ितों, उनके परिवारों और राहत कार्य में जुटे

आपातकालीन कर्मियों के प्रति संवेदना जताई। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने हादसे को बेहद दुखद बताया हुए कहा कि यूरोप इस कठिन समय में स्पेन के साथ है। इटली के विदेश मंत्री एंतेोनियो तजानी ने दुर्घटना पर गहरी चिंता जताई। मैड्रिड स्थित इतालवी वाणिज्य दूतावास संभावित रूप से प्रभावित इतालवी नागरिकों की जानकारी जुटा रहा है। अमेरिका के स्पेन में राजदूत बेंजामिन लियोन जूनियर ने भी दुख व्यक्त किया और राहतकर्मियों के प्रयासों के प्रति समर्थन जताया। ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम सहित कई अन्य देशों ने भी शोक संदेश भेजे। घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है।

नेपाल में 44 हिमालयी चोटियों पर चढ़ाई के लिए 76 देशों के 1,410 पर्वतारोहियों को मिली अनुमति

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल में शरद ऋतु के दौरान 44 हिमालयी चोटियों पर चढ़ाई के लिए 76 देशों के 1,410 पर्वतारोहियों ने अनुमति ली है। इस सीजन में पर्वतारोहण के लिए कुल 161 दलों को अनुमति दी गई है। पर्यटन विभाग की शाखा अधिकारी सुधा रेग्मी ने बताया कि 44 हिमालयी चोटियों पर चढ़ाई के लिए 1,069 पुरुषों और 341 महिलाओं ने अनुमति ली है। पर्वतारोहण की अनुमति जारी करने के बदले विभाग ने पर्वतारोहियों से 31 करोड़ 80 लाख 50 हजार 778 रुपये रॉयल्टी के रूप में एकत्र किए हैं।अनुमति प्राप्त चोटियों में सबसे अधिक पर्वतारोही 8,163 मीटर ऊंचे मनास्लु पर्वत पर चढ़ाई के लिए तैयार हैं। मनास्लु के लिए ही 43 दलों के 500 पर्वतारोहियों ने अनुमति ली है। इनमें 373 पुरुष और 127 महिलाएं शामिल हैं। विभाग ने इनसे 22 करोड़ 58 लाख 57 हजार 189 रुपये रॉयल्टी एकत्र की है।

इसी तरह, धौलागिरि–1 पर चढ़ाई के लिए छह दलों के 37 लोगों ने अनुमति ली है। उनसे विभाग को 84 लाख 73 हजार 650 रुपये रॉयल्टी प्राप्त हुई है। मकालु पर्वत पर चढ़ाई के लिए एक दल के तीन लोगों ने अनुमति ली है। उनसे छह लाख 88 हजार 50 रुपये राजस्व प्राप्त हुआ है। विभाग के अनुसार इन हिमालयी चोटियों पर चढ़ाई के लिए जारी अनुमतियों से 20 लाख 89 हजार 584 अमेरिकी डॉलर, यानी लगभग 31 करोड़ 80 लाख 50 हजार रुपये रॉयल्टी के रूप में एकत्र की गई है। शाखा अधिकारी

लमजुंग हिमाल, पुमोरी, सारिबुंग, थापा पीक (धाम्पुस), पोखर खांग, अर्दगं, जुगल और पेरी सहित अन्य चोटियों पर चढ़ाई के लिए भी अनुमति जारी की गई है। विभाग के अनुसार पर्वतारोहण की अनुमति लेने वालों में चीन के सबसे अधिक 141 नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा रूस के 108, फ्रांस के 130, अमेरिका के 119, ब्रिटेन के 96, पोलैंड के 41, नेपाल के 33, स्विट्जरलैंड के 47, स्पेन के 31, भारत के गंगापूर्णा पश्चिम (लांगचेनेल), थोरोड पीक, नोर्बु खांग, अन्नपूर्णा–4, चामलांग,

लमजुंग हिमाल, पुमोरी, सारिबुंग, थापा पीक (धाम्पुस), पोखर खांग, अर्दगं, जुगल और पेरी सहित अन्य चोटियों पर चढ़ाई के लिए भी अनुमति जारी की गई है। विभाग के अनुसार पर्वतारोहण की अनुमति लेने वालों में चीन के सबसे अधिक 141 नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा रूस के 108, फ्रांस के 130, अमेरिका के 119, ब्रिटेन के 96, पोलैंड के 41, नेपाल के 33, स्विट्जरलैंड के 47, स्पेन के 31, भारत के गंगापूर्णा पश्चिम (लांगचेनेल), थोरोड पीक, नोर्बु खांग, अन्नपूर्णा–4, चामलांग,

नेपाल में भारी बारिश के पूर्वानुमान के बीच सातों प्रांतों को तैयारी मजबूत करने का निर्देश

काठमांडू। नेपाल की स्वास्थ्य आपातकालीन एवं आपदा प्रबंधन इकाई ने स्वास्थ्य विभाग से हाई अलर्ट पर रहते हुए आपदा से निपटने की तैयारियों और राहत कार्यों को प्रभावी बनाने का आग्रह किया है। इकाई ने इस संबंध में देश के सभी सात प्रांतों के प्रांतीय स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्रों को सर्कुलर जारी किया है।

नेपाल के विभिन्न स्थानों पर 29 अक्टूबर से लगातार तीन दिनों तक मध्यम से भारी बारिश, आकाशीय बिजली और तूफान की संभावना जताए जाने के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारियों को मजबूत करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, सभी प्रांतों के केंद्रों को स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित घटनाओं और स्थिति की दैनिक रिपोर्ट अनिवार्य रूप से ‘जिरो रिपोर्टिंग’ या ‘ईसिडेंट रिपोर्टिंग’ के माध्यम से प्रस्तुत करने को कहा गया है। मौसम विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संभावित भारी बारिश, आकाशीय भूस्खलन, बाढ़ और जलभराव जैसी आपदाओं के खतरे को देखते हुए सभी से सतर्क रहने की अपील की है। इकाई प्रमुख डॉ. हेमंत चंद्र ओझा की ओर से जारी सर्कुलर में चौबीसों घंटे संपर्क में रहने के लिए एक आपातकालीन संपर्क अधिकारी

नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, संबंधित अधिकारी का संपर्क विवरण इकाई को उपलब्ध कराने और सार्वजनिक करने को कहा गया है।

इकाई ने आवश्यक स्वास्थ्य संसाधनों के साथ आपातकालीन चिकित्सा टीम को तैयार रखने तथा स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सहयोगी संगठनों के साथ समन्वय कर उपलब्ध मानव संसाधन, दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों, एंबुलेंस और अन्य संसाधनों का विवरण अद्यतन रखने को भी कहा है। सर्कुलर में सभी प्रांतीय स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्रों को एंबुलेंस डिस्पैच सेंटर के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने और एंबुलेंस सेवाओं की सुगम, त्वरित एवं प्रभावी तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य आपदा के दौरान घायलों और प्रभावित नागरिकों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इकाई ने संभावित आपदा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान रोकने, आवश्यक स्वास्थ्यकर्मियों और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत एवं चिकित्सा सहायता पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत करने पर भी जोर दिया है।

हिमालयी आपदाओं की निगरानी और समय पर चेतावनी के लिए नेपाल ने बैंकॉक में क्षेत्रीय सहयोग के तीन प्रस्ताव रखे

काठमांडू। नेपाल ने उपग्रह आधारित जलवायु जोखिम निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए क्षेत्रीय सहयोग के तीन प्रस्ताव रखे हैं। इनमें हिमालयी आपदाओं की निरंतर निगरानी, उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का बेहतर उपयोग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तक सभी देशों की समान पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। नेपाल के ऊर्जा मंत्री बिराज भक्त श्रेष्ठ ने थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में संयुक्त राष्ट्र एशिया एवं प्रशांत आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन एस्कैप) की ओर से आयोजित सतत विकास के लिए अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर पांचवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में ये प्रस्ताव प्रस्तुत किए। श्रेष्ठ ने संवेदनशील पर्वतीय ढलानों और हिमनद झीलों की व्यवस्थित उपग्रह निगरानी, उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों को उपयोगी सूचनाओं में बदलने की विश्लेषण क्षमता मजबूत करने तथा अपने उपग्रह संचालित नहीं करने वाले देशों सहित सभी देशों को अंतरिक्ष आधारित सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि केवल आपदाओं के खतरों का पता लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समय पर चेतावनी जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों तक पहुंचना भी जरूरी है। नेपाल में आपदा प्रबंधन के अनुभवों का उल्लेख करते हुए श्रेष्ठ ने बताया कि अगस्त और अक्टूबर में पूर्व चेतावनी के तहत भेजे गए टेक्स्ट संदेशों की मदद से नौ लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में सहायता मिली। उन्होंने दूरदराज के क्षेत्रों में उपग्रह तस्वीरों और ड्रोन के जरिए किए गए आकलन, नदी में बाढ़ के



पूर्वानुमान में सुधार तथा जोखिम वाले क्षेत्रों के मोबाइल फोन पर एक साथ आपातकालीन अलर्ट भेजने के लिए सेल ब्रॉडकास्टिंग प्रणाली शुरू करने की तैयारियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (आईसीआईएमओडी) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र में उच्च जोखिम वाली चिह्नित 47 हिमनद झीलों में से 21 नेपाल में हैं। श्रेष्ठ के अनुसार छो रोलपा, लोअर बरुण, लुमडिंग और हांगु हिमनद झीलों के जलस्तर को कम करने का काम शुरू कर दिया गया है। श्रेष्ठ ने कहा कि नेपाल हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लगभग दो अरब लोगों के समुदायों की सुरक्षा के लिए

संयुक्त परियोजनाओं और क्षेत्रीय पहलों पर काम करने तथा वर्ष 2030 तक एशिया–प्रशांत कार्ययोजना को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। नेपाल और यूएन एस्कैप गुव्कार को संयुक्त रूप से एक कार्यशाला भी आयोजित करने वाले हैं। इसमें भोटेकोशी–त्रिशुली आपदा से मिले सबक पर चर्चा की जाएगी, ताकि पूरे क्षेत्र में एक आपदा से दूसरी आपदा के पैदा होने और उसके प्रभाव के फैलने के जोखिम को रोक़ा जा सके। श्रेष्ठ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से आयोजित एक अन्य संगोष्ठी को भी संबोधित करेंगे। इसमें नेपाल की पुनर्बहाली और पुनर्निर्माण संबंधी जरूरतों पर चर्चा होगी। उनके शनिवार को स्वदेश लौटने का कार्यक्रम है।

नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा पर समन्वय बैठक आज से, एसएसबी के महानिदेशक काठमांडू पहुंचे

काठमांडू। नेपाल और भारत के बीच सीमा समन्वय संबंधी सुरक्षा बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत के सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के महानिदेशक संजय सिंघल काठमांडू पहुंचे हैं। नेपाल के सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) और भारत के एसएसबी के बीच बुधवार से काठमांडू में सीमा सुरक्षा संबंधी समन्वय बैठक शुरू हो रही है। सीमा सुरक्षा में तैनात दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच यह उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक पिछले एक दशक से हर साल आयोजित होती रही है। इस बार दसवीं समन्वय बैठक होने जा रही है। बैठक में गृह मंत्रालय, सुरक्षा एजेंसियों और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। नेपाल–भारत की खुली सीमा से दोनों देश लाभ उठाते रहे हैं। हालांकि, खुली सीमा का दुरुपयोग कर आपराधिक गतिविधियां भी की जाती हैं। खुली सीमा के जरिए मानव तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, सीमा शुल्क की चोरी, अवैध निर्यात–आयात और अवैध व्यापार दोनों देशों के लिए चुनौती बने हुए हैं।

दूसरी ओर, नेपाल भारत से होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण के लिए प्रभावी सहयोग और सूचनाओं के आदान–प्रदान का मुद्दा उठाने की तैयारी में है। नेपाल सीमापार से आने वाले मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए भारतीय पक्ष से और अधिक सहयोग चाहता है। वहीं, भारत आतंकवाद, अवैध घुसपैठ, सीमावर्ती क्षेत्रों में अनधिकृत आवाजाही और नेपाल से होने वाले शराब के अवैध कारोबार को प्रमुख एजेंडे में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। गंभीर अपराधों में शामिल लोगों के दोनों देशों में

जाकर छिपने की समस्या पर भी बैठक में चर्चा होने की संभावना है। बैठक में तीसरे लेने के लिए भारत के सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के महानिदेशक संजय सिंघल काठमांडू पहुंचे हैं। नेपाल के सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) और भारत के एसएसबी के बीच बुधवार से काठमांडू में सीमा सुरक्षा संबंधी समन्वय बैठक शुरू हो रही है। सीमा सुरक्षा में तैनात दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच यह उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक पिछले एक दशक से हर साल आयोजित होती रही है। इस बार दसवीं समन्वय बैठक होने जा रही है। बैठक में गृह मंत्रालय, सुरक्षा एजेंसियों और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। नेपाल–भारत की खुली सीमा से दोनों देश लाभ उठाते रहे हैं। हालांकि, खुली सीमा का दुरुपयोग कर आपराधिक गतिविधियां भी की जाती हैं। खुली सीमा के जरिए मानव तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, सीमा शुल्क की चोरी, अवैध निर्यात–आयात और अवैध व्यापार दोनों देशों के लिए चुनौती बने हुए हैं।

इस बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों में दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को और प्रभावी बनाने पर चर्चा की तैयारी है। संयुक्त सीमा गश्त, सीमा स्तंभों की मरम्मत, सीमापार अपराधों की रोकथाम, सूचनाओं का प्रभावी आदान–प्रदान और दोनों सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल जैसे मुद्दों पर भी विचार–विमर्श होगा। सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय हलचोक के अनुसार, बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों में आपदा की पूर्वतैयारी और उससे निपटने, सुरक्षा कर्मियों की क्षमता बढ़ाने, प्रशिक्षण में सहयोग तथा अवैध पदार्थों की तस्करी रोकने के उपायों पर भी चर्चा होगी। नेपाल और भारत के बीच वर्ष 2012 से वार्षिक समन्वय बैठक आयोजित होती रही है। कोविड–19 महामारी समेत कुछ कारणाों से प्रभावित अवधि को छोड़कर यह बैठक नियमित रूप से होती रही है। पिछले वर्ष नौवीं समन्वय बैठक भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुई थी।

एक नजर

समाज और राज्य जितना शिक्षित होगा, उतना ही विकसित होगा : नीतीश कुमार



पटना,एजेंसी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बिहारशरीफ, नालंदा स्थित उदंतपुरी में सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में नीतीश कुमार ने सर्वप्रथम सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके उपरांत उन्होंने सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज के संस्थापक प्राचार्य प्रो. राजेन्द्र प्रसाद जी की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने नालंदा सांसद निधि से निर्मित ब्रिज एवं पथ निर्माण कार्य, नवनिर्मित वॉलीबॉल एवं बैडमिंटन कोर्ट एवं नवीनीकृत विज्ञान ब्लॉक का उद्घाटन किया और पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस अवसर पर नीतीश कुमार ने कहा कि पिछले दो दशकों में हमलोगों का निरंतर प्रयास रहा है कि बिहार के बच्चे बाहर नहीं जाएं, यहीं उन्हें अच्छी शिक्षा मिले। इसके लिए हमलोगों ने आधारभूत संरचना के विकास से लेकर शिक्षकों की नियुक्ति, अनेकों छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाओं की शुरुआत, कौशल विकास जैसे तमाम कार्य किए। नालंदा तो वैसे भी पूरे विश्व को ज्ञान दे चुका है, हमें उसी परंपरा को फिर से मजबूत करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरदार पटेल जी की स्मृति में स्थापित एवं संस्था आने वाले वर्षों में उनके आदर्शों और विचारों के अनुरूप मील के औं भी कई पत्थर स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि हमारा समाज और राज्य जितना शिक्षित होगा, उतना ही विकसित होगा। हमारे बच्चे अपने छात्रजीवन में जो बोएंगे वही जीवन भर काटेंगे, इसलिए उन्हें पूरी लगन और निष्ठा से अपना काम करना चाहिए और इसमें परिवार से लेकर सरकार तक, हर किसी को हरसंभव सहायता और प्रोत्साहन देना चाहिए। इस दौरान बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार, विधान परिषद् में सत्तारूढ़ दल के उपनेता ललन सर्राफ, सांसद कौशलेन्द्र कुमार, बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव हरेन्द्र बहादुर सिंह, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ उषेन्द्र प्रसाद सिंह एवं कॉलेज के प्राचार्य डॉ महेश प्रसाद सिंह सहित कई गणमान्य मौजूद रहे।

वडोदरा में सोनी परिवार के तीन सदस्यों की मौत, घर में मिले मां-बेटे और बेटी के शव

वडोदरा। गुजरात के वडोदरा शहर के चार दरवाजा इलाके की नरसिंहजी की पोल स्थित दला पटेल की पोल में सोनी परिवार के तीन सदस्यों की मौत से हड़कंप मच गया। बुधवार शाम आरतीबेन की (50), उनके बेटे नीलकंठ सोनी (23) और बेटी जेनी सोनी (20) के शव घर में फंदे से लटक मिले। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तीनों की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। जानकारी के मुताबिक, परिवार के तीनों सदस्य पिछले दो दिनों से घर से बाहर नहीं निकले थे। घर बंद रहने पर स्थानीय लोगों को संदेह हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को घर के अंदर तीनों के शव मिले। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित पुलिस का काफिला मौके पर पहुंचा। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आरतीबेन के पति चेतनभाई सोनी का करीब एक साल पहले हृदय रोग के कारण निधन हो गया था। इसके बाद परिवार पुराने पादरा रोड पर आयुर्वेदिक दवाओं के कारोबार से जुड़ा हुआ था। आरतीबेन का बेटा नीलकंठ पढ़ाई के लिए कनाडा गया था, लेकिन पिता के निधन के बाद वह वापस लौट आया था और यहीं रह रहा था। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस ने बताया कि पुलिस तीनों की मौत के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।

भारत की सांस्कृतिक चेतना और ज्ञान परंपराएं हमारी सम्यतागत निरंतरता की नींव: गजेंद्र सिंह शेखावत

नई दिल्ली। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत की पहचान केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही सांस्कृतिक चेतना, ज्ञान परंपराओं, आध्यात्मिक साधना और ऐतिहासिक अनुभवों से निर्मित हुई है। भारत की सभ्यता और संस्कृति ने सदियों से निरंतर प्रवाह बनाए रखा है और दुनिया को विभिन्न सभ्यताओं के साथ संवाद एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से अपने संबंध स्थापित किए हैं।

यह बात आज उन्होंने नई दिल्ली के मंडी हाउस स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के धरोहर भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण और पुनरुत्थान पर केंद्रित पुस्तक ‘टाइमलेस इंडिया: प्रोटेक्शन एंड रिवाइवल ऑफ इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी’ का विमोचन किया गया। पुस्तक का प्रकाशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) एवं सुधी पब्लिकेशंस ने किया है, जबकि इसके संपादक तर्पण विजय हैं। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और आईजीएनसीए के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ.



जितेंद्र सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे ने मुख्य वक्तव्य दिया। सांस्कृतिक चिंतक डॉ. अनिल गोयल ने सत्र की अध्यक्षता की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक वाई. एस. रावत और दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. रमेश सी. गौर सहित कई विद्वान और बुद्धिजीवी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीयों के मन में अपनी सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं के प्रति गौरव की भावना को कमजोर करने के प्रयास किए गए। इसका प्रभाव भारतीय ज्ञान परंपराओं और

सांस्कृतिक आदर्शों को देखने के नजरिए पर भी पड़ा। उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता की विशेषता यह है कि वह अतीत से प्रेरणा लेते हुए भविष्य की ओर आगे बढ़ती है। भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण के आदर्शों के साथ ऋषियों, विचारकों और ज्ञान के साधकों की परंपरा आज भी भारत की सांस्कृतिक चेतना का महत्वपूर्ण आधार है। भारत की स्थापत्य कला, ज्ञान परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत ने विश्वभर के देशों को आकर्षित किया है।

डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि भारत की प्राचीन संस्कृति और उसकी कालजयी यात्रा को समझने के लिए अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता और गौरव का भाव आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद लंबे समय

तक भारतीय संस्कृति के बारे में खुलकर बात करने में एक प्रकार की झिझक बनी रही, जिसके कारण औपनिवेशिक मानसिकता से पूरी तरह बाहर निकलने की प्रक्रिया प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि ‘टाइमलेस इंडिया’ जैसी पुस्तकें भारत की सांस्कृतिक निरंतरता और भारतीयता के मूल स्वरूप को समझने का अवसर प्रदान करती हैं। उन्होंने प्रसिद्ध लेखक मार्क टुली की पुस्तक ‘नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया’ का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय समाज की विशेषता आम लोगों की आस्था और उनके जीवन के अनुभवों को समझने में है। डॉ. सहस्त्रबुद्धे ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय संस्कृति को केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसे शिक्षा और दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इसके लिए मातृभाषा में शिक्षा को प्रोत्साहित करने और विद्यार्थियों तक भारतीय जीवन, संस्कृति तथा परंपराओं से जुड़ी सामग्री पहुंचाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉ. अनिल गोयल ने कहा कि भारत एक प्राचीन सभ्यता है, जिसकी सांस्कृतिक चेतना हजारों वर्षों से चली आ रही जीवंत परंपराओं में दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि मंदिर, स्तूप, किले, मूर्तियां और अभिलेख केवल ऐतिहासिक स्मारक नहीं हैं, बल्कि वे हमारे पूर्वजों के ज्ञान, कला, विज्ञान, आस्था और दर्शन के प्रमाण भी हैं।

गैरसैंण में दो सत्र आयोजित करना सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक: पुष्कर सिंह धामी

भराड़ीसैंण (गैरसैंण)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को विधानसभा सत्र के समापन के बाद कहा कि गैरसैंण में एक वर्ष में दो विधानसभा सत्रों का आयोजन राज्य सरकार का प्रतीक है। उन्होंने विपक्ष से सदन की गरिमा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान करने की अपील करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने के बजाय हंगामा और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को प्राथमिकता दे रही है।

मुख्यमंत्री ने भराड़ीसैंण में पात्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार गैरसैंण के विकास और प्रदेश की जनभावनाओं के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले पांच वर्षों में गैरसैंण के विधानसभा सत्रों के आयोजन को विशेष महत्व दिया गया है। सरकार का प्रयास है कि सदन में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा हो तथा आवश्यक निर्णय लिए जाएं। उन्होंने आयोजन को विशेष महत्व दिया गया महत्वपूर्ण मंच है और जनप्रतिनिधियों को जनता से जुड़े मुद्दे गंभीरता एवं जिम्मेदारी से उठाने चाहिए। विरोध करना विपक्ष का



अधिकार है, लेकिन यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप होना चाहिए। सदन की कार्यवाही बाधित होने से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा प्रभावित होती है। धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने, सख्त भू-कानून बनाने तथा शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की दिशा में कदम उठाए हैं। वर्ष 2022 में जनता के समक्ष रखे गए दृष्टिपत्र के अनुरूप सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि यूसीसी के माध्यम से सामाजिक समानता और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में पहल की गई है। सरकार सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य

हीनभावना रखना उचित नहीं है। सनातन की मूल भावना समन्वय, सह-अस्तित्व, करुणा और विश्व कल्याण की है। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को किसी पूर्वाग्रह के चशमे से नहीं देखा जाना चाहिए। वेदों का संदेश किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा देता है। सनातन परंपरा ने सदियों से विचारों के आदान-प्रदान, आध्यात्मिक चिंतन और ज्ञान की विभिन्न धाराओं को स्थान दिया है। भारत की सांस्कृतिक विरासत अतीत की धरोहर के साथ वर्तमान और भविष्य के लिए भी मार्गदर्शक है। योग, आयुर्वेद, अध्यात्म और वैदिक ज्ञान की प्रासंगिकता आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है। स्वामी रामदेव ने आरोप लगाया कि कुछ लोग धर्मशास्त्रों और पुराणों के संदर्भों में बदलाव कर ऐसी बातें प्रस्तुत करते हैं, जिससे सनातन धर्म और आराध्य देवी-देवताओं की छवि प्रभावित होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम और माता सीता को मांसाहार एवं मदिरापान से जोड़कर प्रस्तुत करना, भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य महारास को गलत संदर्भ में अपभ्रंश बताना और महायोगी शिव को नशे से जोड़कर दिखाना इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि धार्मिक विषयों पर धारणा बनाने से पहले मूल संदर्भों और प्रमाणों को समझना जरूरी है।

यूनेस्को के नाम पर दुर्गा पूजा पास घोटाला: पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन ईडी दफ्तर में पेश

कोलकाता,एजेंसी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन बुधवार को कोलकाता के साल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय में पेश हुए। वे अपने साथ मामले से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी लेकर पहुंचे थे। ईडी उनके खिलाफ यूनेस्को के नाम का दुरुपयोग कर दुर्गा पूजा के पास बेंचने से जुड़े करोड़ों रुपये के कथित घोटाले की जांच कर रही है। दिलचस्प बात यह रही कि ईडी दफ्तर के बाहर कोलकाता पुलिस के अधिकारी भी तैनात नजर आए। इस बहुचर्चित मामले में चंदननगर के पूर्व विधायक इंद्रनील सेन पर मुख्य आरोपित के रूप में करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप है।

इससे पहले भी ईडी उनसे कई बार पूछताछ कर चुकी है और उनके कस्बा स्थित आवास व सिंगूर के फार्महाउस सहित कई ठिकानों पर सघन छापेमारी की जा चुकी है। दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा के संपन्न होने के तुरंत बाद जांच एजेंसी ने उन्हें फिर से तलब किया था, जिसके अनुपालन में उन्होंने बुधवार को हाजिरी लगाई। इंद्रनील सेन के खिलाफ पूजा पास घोटाले की मूल शिकायत कोलकाता पुलिस के बौबाजार थाने में जयदीप मुखर्जी नामक व्यक्ति ने दर्ज कराई थी। इसी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई और बाद में वित्तीय अनियमितताओं को देखते हुए ईडी ने भी जांच शुरू कर दी। हालांकि, बुधवार को इंद्रनील के सीजीओ कॉम्प्लेक्स पहुंचने के बाद वहां कोलकाता पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी



का कारण अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सका है। ईडी और पुलिस की तेज होती जांच के बीच गिरफ्तारी की आशंका के चलते इंद्रनील सेन ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद आरोपित नेता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन शीर्ष अदालत से भी उन्हें अब तक कोई राहत नहीं मिल सकी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया।

इससे कानूनी जटिलताएं और बढ़ गई हैं। इसी रस्साकशी के बीच उन्हें ईडी के सामने पेश होना पड़ा है। प्रारंभिक जांच के आधार पर ईडी का अनुमान है कि यह पूरा घोटाला लगभग 50 से 60 करोड़ रुपये का है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि इंद्रनील दुर्गा

पूजा के ‘प्रिन्सी शो’ और ‘प्रिविलेज्ड पूजा एंटी’ के नाम पर ‘फर्जी’ टिकट और पास बेचकर भारी रकम वसूलते थे। इस कथित भ्रष्टाचार में उनकी पत्नी मधुछंदा सेन के भी शामिल होने का आरोप है। मधुछंदा ‘मास आर्ट’ नामक संस्था से जुड़ी हैं, जिसका गठन 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की मान्यता मिलने के तुरंत बाद किया गया था। ईडी का दावा है कि इसी ‘मास आर्ट’ संस्था के माध्यम से भ्रष्टाचार का यह खेल चला। प्रचार में लोगों को यह झांसा दिया जाता था कि उनका सीधा यूनेस्को से गठजोड़ है और इस आयोजन को यूनेस्को की मंजूरी प्राप्त है। जबकि हकीकत यह है कि यूनेस्को ने ऐसा कोई भी व्यावसायिक या वाणिज्यिक समझौता नहीं किया था। इस हाई-प्रोफाइल मामले में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम भी सामने आ चुका है। ‘मास आर्ट’ मामले की जांच के दौरान ईडी ने एक आधिकारिक बयान में दावा किया था कि आरोपित इंद्रनील सेन की संस्था से ममता बनर्जी को 30 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। जांच एजेंसी के अनुसार, जब इंद्रनील मंत्री पद पर थे, तब उनके और उनके स्वामित्व वाली कंपनी ‘ऑक्टेव रिक्तोईस’ के बैंक खातों में कुल 3.8 करोड़ रुपये जमा हुए थे। बाद में उसी कंपनी के खाते से तत्कालीन मुख्यमंत्री के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए। हालांकि, इन वित्तीय लेन-देन पर सफाई देते हुए आरोपित इंद्रनील सेन ने दावा किया था कि वह पैसा ममता बनर्जी को ‘रॉयल्टी’ के रूप में दिया गया था।

हरियाणा को गुजरात से मिले 50 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव

चंडीगढ़,एजेंसी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दो दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान प्रदेश को निवेश के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है। गुजरात के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ हुई बैठकों के सकारात्मक परिणामस्वरूप हरियाणा में 50 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों से संबंधित समझौता पत्राणों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन निवेश प्रस्तावों से प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलने के साथ-साथ रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री बुधवार को गुजरात के गांधीनगर में बिजनेस लीडर्स और निवेशकों के साथ वन-टू-वन बैठक कर रहे थे। इस मौके पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे।

बुधवार को हुए एमओयू में मुख्य रूप से डिफेंस, रियल एस्टेट और ऑयल एंड गैस क्षेत्र में लगभग 25,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा, एग्रीकल्चर एवं फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में 1,400 करोड़ और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 2,900 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कंस्ट्रूड बायोगैस और सिविल एंक्विशन क्षेत्रों में भी निवेश के लिए एमओयू किए गए हैं। दौरे के पहले दिन भी लगभग 12,000 करोड़ से संबंधित एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे। नायब सिंह सैनी ने गुजरात प्रवास के दौरान विभिन्न उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ वन-टू-वन बैठकें कीं और उन्हें हरियाणा में अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने निवेशकों को राज्य की उद्योग-अनुकूल नीतियों, मजबूत बुनियादी ढांचे, बेहत



कनेक्टिविटी, कुशल मानव संसाधन और अनुकूल कारोबारी वातावरण की जानकारी दी। उन्होंने आश्चर्य किया कि हरियाणा सरकार उद्योगों की स्थापना और निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरल प्रक्रियाएं, डिजिटल सुविधाएं तथा नियमानुसार आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हरियाणा को निवेश, उद्योग और विनिर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बनते हुए रोजगार के नए अवसर सृजित करना और प्रदेश की आर्थिक प्रगति को नई गति प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा और गुजरात, दोनों ही राज्य उद्यमशीलता, विनिर्माण और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। दोनों राज्यों के उद्योगपतियों के

बीच सहयोग बढ़ने से निवेश, तकनीकी नवाचार, उत्पादन क्षमता और रोजगार सृजन की नई संभावनाएं विकसित होंगी। मुख्यमंत्री ने गुजरात के उद्योगपतियों और निवेशकों को अप्रैल 2027 में हरियाणा में प्रस्तावित ‘हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल समिट’ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य निवेशकों को एक ऐसा अनुकूल औद्योगिक वातावरण उपलब्ध कराना है, जहां वे बिना किसी बाधा के अपने कारोबार की स्थापना और विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर सकें। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को आश्चर्य किया कि हरियाणा सरकार उद्योग जगत की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और निवेश की पूरी प्रक्रिया में उन्हें हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।